भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस प्रकाशनी - 9 मार्च 2026
Press Release - 9th March 2026

प्राधिकरण की 134वीं बैठक / 134th Meeting of the Authority

प्राधिकरण की 134वीं बैठक 9 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, प्राधिकरण ने विभिन्न विनियामक विषयों पर विचार किया।

दो बीमा संस्थाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान किया गया। प्राधिकरण ने एक पुनर्बीमाकर्ता, मैसर्स आलियांज जियो रीइंश्योरेंस लिमिटेड और एक साधारण बीमाकर्ता, मैसर्स कीवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया, जिससे वे लागू विनियामक ढांचे के अनुसार व्यवसाय करने में सक्षम हो गए।

प्राधिकरण ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) अधिनियम, 2025 ("एसबीएसआर अधिनियम") के अधिनियमन के अनुसार आवश्यक विनियामक ढांचे पर भी विचार-विमर्श किया। एसबीएसआर अधिनियम 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किए गए थे और यह 5 फरवरी 2026 से प्रभावी हुआ। यह कानून बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 में संशोधन करता है, जिससे नए कानून के प्रावधानों के साथ विनियामक ढांचे को संरेखित करने के लिए नए विनियमों के निर्माण और मौजूदा विनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता हो गई है।

विनियामक संरेखण प्रक्रिया में तेजी लाने और एसबीएसआर अधिनियम के सुधारों को शामिल करने के लिए, प्राधिकरण ने एसबीएसआर अधिनियम के अनुसार तैयार किए जाने वाले विनियमों के संबंध में हितधारक परामर्श के लिए मसौदा विनियमों का मसौदा तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

The 134th Meeting of the Authority was held on 9th March 2026. During the meeting, the Authority considered various regulatory matters.

Approval was accorded for the grant of Certificate of Registration to two insurance entities. The Authority accorded approval to one reinsurer, M/s Allianz Jio Reinsurance Limited, and one general insurer, M/s Kiwi General Insurance Limited, enabling them to undertake business in accordance with the applicable regulatory framework.

The Authority also deliberated on the regulatory framework required pursuant to the enactment of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 (“SBSR Act”). The SBSR Act was notified on 21st December 2025 and came into force with effect from 5th February 2026. The legislation amends the Insurance

Act, 1938 and the IRDA Act, 1999, thereby necessitating the framing of new regulations and amendments to existing regulations to align the regulatory framework with the provisions of the new law.

In order to expedite the regulatory alignment process and incorporating reforms of SBSR Act, the Authority granted in-principle approval for drafting and publishing the draft regulations for stakeholder consultation with regard to the regulations which are required to be framed pursuant to SBSR Act.

***